भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3478

बुधवार, 17 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम

3478. सुश्री सुनीता दुग्गल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जा रहे औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं की सूची क्या है और इन औद्योगिक गलियारों की स्थिति क्या है;

(ख) क्या हरियाणा राज्य के लिए किसी औद्योगिक गलियारे की योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन औद्योगिक गलियारों में प्रस्तावित/निर्माणाधीन मल्टी मॉडल लाजिस्टिक हब की सूची क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सोम प्रकाश)

(क): भारत सरकार ने आर्थिक क्षेत्रों को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान के भाग के रूप में 11 कोरिडोर्स (32 परियोजनाओं) को चार चरणों में विकास के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जो अवधारणात्मक/विकास/कार्यान्वन के विभिन्न चरणों में हैं। कार्यान्वयन की स्थिति सहित संबंधित राज्यों में परियोजनाओं की सूची **अनुबंध** में दी गई है।

(ख) और (ग): निम्नलिखित दो औद्योगिक कॉरिडोर हरियाणा राज्य में हैं:

(i) दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर (डीएमआईसी)

(ii) अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर (एकेआईसी)

डीएमआईसी के अंतर्गत, नांगल चौधरी (886 एकड़) में एकीकृत मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब (आईएमएलएच) परियोजना के विकास कार्य शुरू कर दिया गया है। मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है और परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। एकेआईसी के अंतर्गत, राज्य सरकार ने हिसार में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) के विकास के लिए 1,500 एकड़ भूमि की पुष्टि की है। विकास कार्य शुरु हो गया है और मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग के लिए सलाहकार नियुक्त कर दिए गए हैं।

(घ): राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर कार्यक्रम के अंतर्गत, उपर्युक्त के अलावा, डीएमआईसी के तहत उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब (एमएमएलएच) (334 हेक्टेयर) के लिए विकास कार्य शुरु कर दिए गए हैं।

*****

अनुबंध

दिनांक 17.03.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3478 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र. सं.	कॉरीडोर	परियोजनाओं की संख्या	नाम	स्थिति
1	दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर (डीएमआईसी)	10	(1) धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (डीएसआईआर), गुजरात	• 'धोलेरा औद्योगिक शहर विकास लिमिटेड' नामक एसपीवी को निगमित किया गया है • राज्य सरकार ने 44.26 वर्ग किमी. भूमि एसपीवी को हस्तांतरित की है तथा एनआईसीडीआईटी द्वारा 2551.94 करोड़ रुपए के बराबर इक्विटी जारी की गई है • आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने विभिन्न अवसंरचना घटकों के लिए 2784.82 करोड़ रुपए राशि के निविदा पैकेज अनुमोदित किए हैं जिन्हें पांच पैकेजों में बांटा गया है • सड़कों और भूमिगत सुविधाओं की कुल वास्तविक प्रगति 87 प्रतिशत है • भूमि आबंटन नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा 152.71 एकड़ के 03 भूखंड आबंटित किए गए हैं। • आईसीटी मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया गया है तथा विभिन्न स्मार्ट सिटी घटकों के कार्यान्वयन के लिए मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) को नियुक्त किया गया है।
			(2) शेन्द्रा बिदकिन औद्योगिक क्षेत्र (एसबीआईए), महाराष्ट्र	• 'औरंगाबाद औद्योगिक टाउनशिप लिमिटेड' नामक नोड/शहर स्तरीय एसपीवी को निगमित किया गया है • राज्य सरकार ने शेन्द्रा औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए एसपीवी को 8.39 वर्ग किमी. भूमि हस्तांतरित की है तथा एनआईसीडीआईटी द्वारा 602.80 करोड़ रुपए के बराबर इक्विटी जारी की गई है। • शेन्द्रा बिदकिन औद्योगिक क्षेत्र के लिए विभिन्न अवसंरचना घटकों के विकास हेतु आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 1533 करोड़ रुपए के निविदा पैकेज को अनुमोदित किया है। • 78 भूखंड (234 एकड़) आबंटित किए गए हैं तथा 9 कंपनियों ने उत्पादन शुरु कर दिया है और 27 कंपनियों द्वारा निर्माण कार्य शुरु कर दिया है। अन्य भूखंड अधिकांशत: लघु और मध्यम उद्यमों को

				आबंटित किए गए हैं। • माननीय प्रधानमंत्री ने 7 सितंबर, 2019 को शेन्द्रा बिदकिन औद्योगिक क्षेत्र (डीएमआईसी के तहत) राष्ट्र को समर्पित किया। • बिदकिन औद्योगिक क्षेत्र के लिए राज्य सरकार ने 28.75 वर्ग किमी. भूमि एसपीवी को हस्तांतरित की। एनआईसीडीआईटी द्वारा 2397.20 करोड़ रुपए की समान इक्विटी जारी की गई है। • बिदकिन औद्योगिक क्षेत्र के लिए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 31.79 वर्ग किमी. के लिए 6414.21 करोड़ रुपए के अवसंरचना पैकेज को अनुमोदित किया जिसे 3 चरणों में शुरु किया जाना है तथा 10.16 वर्ग किमी. के लिए निर्माण कार्य चल रहा है और सड़क व अन्य सुविधाओं की वास्तविक प्रगति 95 प्रतिशत है।
			(3) एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप - ग्रेटर नोएडा (आईआईटी-जीएन), उत्तर प्रदेश	• 'डीएमआईसी एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड' नामक एसपीवी को निगमित किया गया है। • परियोजना एसपीवी को 747.5 एकड़ भूमि हस्तांतरित की गई है तथा एनआईसीडीआईटी द्वारा 617.20 करोड़ रुपए के बराबर इक्विटी जारी की गई है और सड़क व अन्य सुविधाओं के लिए निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। • भूमि आबंटन नीति को अंतिम रूप दिया जा चुका है तथा 153.89 एकड़ के 05 भूखंड आबंटित किए गए हैं तथा 3 कंपनियों द्वारा निर्माण कार्य शुरु किया जा चुका है। • हरित/ प्रदूषण रहित उद्योगों को अनुमति देने के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि उपयोग में परिवर्तन की प्रक्रिया को अनुमोदित किया गया है।
			(4) एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप - विक्रम उद्योगपुरी (आईआईटी-वीयूएल), मध्य प्रदेश	• 'डीएमआईसी एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड' नामक एसपीवी को निगमित किया गया है। • राज्य सरकार ने 1100 एकड़ भूमि एसपीवी को हस्तांतरित की है तथा एनआईसीडीआईटी द्वारा 55.93 करोड़ रुपए के बराबर इक्विटी और 260.54 करोड़ रुपए के समान ऋण जारी किया है। • सड़क व अन्य सुविधाओं के लिए निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

				• भूमि आबंटन नीति को अंतिम रूप दिया जा चुका है तथा 22.14 एकड़ के 03 भूखंड आबंटित किए गए हैं।
			(5) एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब- नांगल चौधरी, हरियाणा	• राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास और कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) और राज्य सरकार के बीच 'एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट लिमिटेड' नामक एसपीवी को निगमित किया गया है; • परियोजना के लिए मास्टर प्लानिंग पूरी हो चुकी है तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है; • सीसीईए ने चरण I के विकास के लिए 1029.49 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी के साथ परियोजना को अनुमोदित किया है तथा परियोजना के चरण II के विकास को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है।
			(6) मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमएलएच और एमएमटीएस), उत्तर प्रदेश	• एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप परियोजना के लिए एसपीवी एमएमएलएच और एमएमटीएच परियोजनाओं का कार्यान्वयन भी करेगा; • सीसीईए द्वारा 30 दिसंबर, 2020 को परियोजना अनुमोदित की गई;
			(7) दिघी पत्तन औद्योगिक क्षेत्र, महाराष्ट्र	• 3,500 हेक्टेयर के लिए मास्टर प्लानिंग पूरी हो चुकी है। • राज्य सरकार ने 12 नवंबर, 2020 को सूचित किया कि चरण-I में 6327 हेक्टेयर भूमि को विकसित किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें से 3925 हेक्टेयर एमआईडीसी द्वारा विकसित की जाएगी तथा 2402 हेक्टेयर औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड (एआईटीएल) द्वारा विकसित किया जाएगा। यह भी सूचित किया गया था कि 2402 हेक्टेयर भूमि में से 1466 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार के अधिकार में है।
			(8) मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, साणंद, गुजरात	एनआईसीडीआईटी ने 30 अगस्त, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में शेयरधारक करार (एसएचए) को अनुमोदित किया जिसे एनआईसीडीआईटी और गुजरात सरकार के बीच लागू किया जाना है। मास्टर प्लान तैयार करने के लिए क्रियाकलाप शुरु किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने नवंबर, 2020 में 199 हेक्टेयर भूमि

				की उपलब्धता की पुष्टि की है।
			(9) जोधपुरी पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (जेपीएमआईए), राजस्थान	• राज्य सरकार ने 12 अक्टूबर, 2020 को यह सूचित किया कि जेपीएमआईए की विकास योजना को विशेष निवेश क्षेत्र (एसआईआर) के रूप में अधिसूचित किया गया है। • चरण-I के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 1690 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है (1060 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है)। • आरआईआईसीओ (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम) को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है। • जेपीएमआईए (2659 हेक्टेयर) के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग करने तथा तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता हेतु परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए अनुबंध पत्र जारी किया गया है।
			10) खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराना औद्योगिक क्षेत्र (केबीएनआईआर), राजस्थान	• राज्य सरकार ने 12 अक्टूबर, 2020 को सूचित किया कि केबीएनआईआर की विकास योजना को विशेष निवेश क्षेत्र (एसआईआर) के रूप में अधिसूचित किया गया है। • राज्य सरकार द्वारा चरण I के विकास के लिए 658 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है (26 हेक्टेयर अधिग्रहीत)। • आरआईआईसीओ (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम) को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण नियुक्त किया गया है। • केबीएनआईआर की विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग के लिए परामर्शदाताओं के चयन हेतु निविदा जारी की गई है।
2	चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक कॉरीडोर	3	(1) कृष्णपटनम औद्योगिक क्षेत्र, आंध्र प्रदेश	• आंध्र प्रदेश में कृष्णपटनम नोड के लिए, शेयरधारक करार (एसएचए) और राज्य सहायता करार (एसएसए) को लागू किया गया है तथा 'एनआईसीडीआईटी कृष्णपटनम औद्योगिक शहर विकास निगम' नामक एसपीवी को निगमित किया गया है। एक्टीवेशन एरिया (2500.4 एकड़) के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग क्रियाकलापों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। एनआईसीडीआईटी ने 30 अगस्त, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में, परियोजना की समीक्षा की तथा सीसीईए द्वारा अनुमोदित किए जाने हेतु इसकी सिफारिश की।

				सीसीईए द्वारा 30 दिसंबर, 2020 को परियोजना अनुमोदित की गई।
			(2) तुमकुरु औद्योगिक क्षेत्र, कर्नाटक	• कर्नाटक में तुमकुरु नोड के लिए, शेयरधारक करार (एसएचए) और राज्य सहायता करार (एसएसए) को लागू किया गया है तथा परियोजना एसपीवी यथा सीबीआईसी तुमकुरु औद्योगिक टाउनशिप लि. को निगमित किया गया है। एक्टीवेशन एरिया (1736.20 एकड़) के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग को अंतिम रूप दिया जा चुका है। एनआईसीडीआईटी ने 30 अगस्त, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में, परियोजना की समीक्षा की तथा सीसीईए द्वारा अनुमोदित किए जाने हेतु इसकी सिफारिश की। सीसीईए द्वारा 30 दिसंबर, 2020 को परियोजना अनुमोदित की गई।
			(3) पोन्नेरी औद्योगिक क्षेत्र, तमिलनाडु	• तमिलनाडु में पोन्नेरी नोड के लिए शेयरधारक करार (एसएचए) और राज्य सहायता करार को 21 फरवरी, 2020 को अंतिम रूप दिया गया है तथा परियोजना एसपीवी को निगमित किया गया है। इसके अलावा, विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग क्रियाकलापों के लिए परामर्शदाताओं को नियुक्त किया गया है।
3	कोयम्बटूर के रास्ते कोच्चि के लिए सीबीआईसी का विस्तार	2	1.पलक्कड़ औद्योगिक क्षेत्र, केरल 2. धर्मपुरी , तमिलनाडु	• एनआईसीडीआईटी ने दिनांक 30 अगस्त, 2019 की अपनी बैठक में सीबीआईसी परियोजना का कोयम्बटूर के रास्ते कोच्चि तक विस्तार करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। • तद्नुसार, पलक्कड़ (केरल) और धर्मपुरी सलेम (तमिलनाडु) हेतु विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग के लिए सलाहकार नियुक्त कर दिए गए हैं। • दिनांक 22 अक्तूबर, 2020 को केरल सरकार के साथ शेयरधारक समझौता (एसएचए) और राज्य सहायता समझौता (एसएसए) को लागू किया गया है।
4	अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर (एकेआईसी)	7	1. रघुनाथपुर औद्योगिक पार्क, पश्चिम बंगाल 2. हिसार एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर	• एकेआईसी की भावी योजना तैयार कर ली गई है। • तद्नुसार, पश्चिम बंगाल (रघुनाथपुर) के आईएमसी स्थल के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजिनियरिंग का कार्य पूरा

			आईएमसी, हरियाणा 3. प्राग खुरपिया एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर आईएमसी, उत्तराखंड 4. राजपुरा पटियाला आईएमसी, पंजाब 5. आगरा, उत्तर प्रदेश 6. नई बहरी नोड, झारखंड 7. गम्हरिया आईएमसी, बिहार	हो गया है। • खुरपिया नोड (1000 एकड़), उत्तराखंड, हिसार (1500 एकड़), हरियाणा, राजपुरा-पटियाला (1100 एकड़), पंजाब में विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग का कार्य करने के लिए सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। • उत्तर प्रदेश सरकार ने एकेआईसी के अंतर्गत दो स्थलों नामत: आगरा (1000 एकड़) और प्रयागराज (1141 एकड़) के विकास की पुष्टि की है। • झारखंड सरकार से विकास के लिए एक वैकल्पिक स्थल का सुझाव देने का भी अनुरोध किया गया है क्योंकि पहले चिह्नित स्थल (बरही) विकास के लिए व्यवहार्य नहीं है।
5	हैदराबाद नागपुर औद्योगिक कॉरीडोर (एचएनआईसी)	1	जहीराबाद चरण 1, तेलंगाना	• जैसा कि निर्णय लिया गया था, तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद वारंगल और हैदराबाद नागपुर औद्योगिक कोरीडोर के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और उचित भूमि की पहचान कर ली है। • हैदराबाद वारंगल औद्योगिक कोरीडोर के भाग रूप में हैदराबाद फार्मा सिटी की पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त, हैदराबाद नागपुर औद्योगिक कोरीडोर के भाग के रूप में जहीराबाद की पहचान की गई है। • अध्ययन के आधार पर हैदराबाद वारंगल और हैदराबाद नागपुर औद्योगिक कोरीडोर को शामिल करने से संबंधित प्रस्ताव पर विचार किया गया था और 19 अगस्त, 2020 को एनआईसीडीआईटी ने अपनी बैठक में अनुमोदन प्रदान किया था।
6	हैदराबाद वारंगल ओद्योगिक कॉरिडोर (एचडबल्यूआईसी)	1	हैदराबाद, चरण 1, तेलंगाना	
7	हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर (एचबीआईसी)	1	ओरवाकल औद्योगिक कॉरीडोर, आंध्र प्रदेश	• एनआईसीडीआईटी ने 19 अगस्त, 2020 को एनआईसीडीआईटी के अधिदेश के अंतर्गत एचबीआईसी के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है। • तद्नुसार, ओरवाकल नोड (आंध्र प्रदेश) के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजिनियरिंग हेतु सलाहकार नियुक्त किए गए हैं।
8	बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर	2	(1) धारवाड़ नोड, कर्नाटक	• भावी योजना तैयार की ली गई है। • कर्नाटक सरकार ने विकास के लिए प्राथमिकता नोड

	(बीएमआईसी)		(2) सतारा नोड, महाराष्ट्र	के रूप में धारवाड़ की पहचान की है। महाराष्ट्र सरकार ने प्राथमिकता नोड के रूप में सतारा का सुझाव दिया है।
9	विजाग चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर (वीसीआईसी)	3	1. कोपरथी औद्योगिक क्षेत्र, आंध्र प्रदेश 2. विशाखापत्तनम औद्योगिक क्षेत्र, आंध्र प्रदेश 3. चित्तूर औद्योगिक क्षेत्र, आंध्र प्रदेश	• कोलकाता-चेन्नई-तूतीकोरिन को जोड़ने वाले पूर्वी तटीय आर्थिक कॉरिडोर के भाग के रुप में परिकल्पना की गई है।; • एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने संकल्पना विकास योजना (सीडीपी) तैयार की है और विकास के लिए निम्नलिखित नोड्स की पहचान की है। • विशाखापट्टनम • मछलीपट्टनम • दोनाकोंडा • चित्तूर • एनआईसीडीआईटी ने 30 अगस्त, 2019 की अपनी बैठक में वीसीआईसी के चरण-1 में प्राथमिकता नोड के रूप में विशाखापट्टनम और चित्तूर के विकास के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। • राज्य सरकार ने एनआईसीडीआईटी की बैठक में आंध्र प्रदेश राज्य के एक अतिरिक्त नोड के रूप में कोपर्थी को शामिल करने का भी अनुरोध किया है। • राज्य सरकार ने औद्योगिक नोड के विकास के लिए कोपर्थी और चित्तूर में भूमि की उपलब्धता के संबंध में सूचित किया है और तदनुसार, दो स्थलों के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग हेतु सलाहकार नियुक्त कर दिए गए हैं। • विशाखापटनम स्थल के लिए, राज्य सरकार विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियां कर रही है।
10	ओडिशा आर्थिक गलियारा (ओईसी)	1	पारादीप - केंद्रपाड़ा - धामरा- सुबर्णरेखा और ओडिशा गोपालपुर-भुवनेश्वर-कलिंगनगर, ओडिशा	• एडीबी द्वारा संकल्पना विकास योजना (सीडीपी) को अंतिम रुप दिया गया है। • विकास के लिए गोपालपुर-भुबनेश्वर-कलिंगनगर (जीबीके) और पारादीप-केंद्रपाड़ा-धमरा-सुबर्नरेखा (पीकेडीएस) की पहचान की गई है। • एनआईसीडीआईटी ने दिनांक 19 अगस्त, 2020

				के समग्र अधिदेश के रुप में ओईसी को शामिल किए जाने को अनुमोदन प्रदान किया है। • जीबीके और पीकेडीएस नोड के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग हेतु एलओए प्रदान किया गया है।
11	दिल्ली नागपुर औद्योगिक कॉरीडोर (डीएनआईसी)	1	यह परियोजना संकल्पनाधीन स्तर पर है।	

*****